GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 270
TO BE ANSWERED ON THE 25TH NOVEMBER, 2014

CULTIVATION OF PALM

270. DR. NEPAL SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE कृषि मंत्री
be pleased to state:

(a) whether the Government has formulated any scheme to promote the cultivation of Palm across the country;

(b) if so, the details thereof, State-wise; and

(c) the success achieved in increasing the production of Palm therefrom?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (DR. SANJEEV KUMAR BALYAN)

(a) to (c): Yes, Madam. In order to promote cultivation of oil palm in the country, Government of India implemented Oil Palm Development Programme (OPDP) from 1991-92 to 2003-04, Integrated Scheme for Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize (ISOPOM) from 2004-05 to 2013-14 and Oil Palm Area Expansion (OPAE) from 2011-12 to 2013-14. In XIIth Five Year Plan, National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) is being implemented from 2014-15.

Under Mini Mission–II (Oil Palm) of NMOOP, assistance is provided for purchase of planting material, maintenance for gestation period, installation of drip-irrigation system, diesel / electric pump-sets, bore-well / water harvesting structure/ponds, inputs for inter-cropping in oil palm fields, construction of vermi-compost units, training, demonstration, establishment of new seed garden, purchasing of machinery & tools and setting up of oil palm processing units in NE/hilly States/LW areas. Directorate of Oil Palm Research (DOPR), Pedavegi, ICAR is providing technical guidance to the implementing States and also supplying the planting material of oil palm.

Area under oil palm cultivation has increased from 8,585 hectare in 1991-92 to 2,50,763 hectare in 2013-14. Similarly, the production of fresh fruit bunches (FFBs) and crude palm oil (CPO) was 21,233 MT and 1,134 MT respectively during the year 1992-93, which has now increased to 9,95,211 MT of FFBs and 1,71,354 MT of CPO during the year 2013-14. During the year 2014-15, Government of India has fixed a target to cover 34,750 hectares area under oil palm in 14 States. The State-wise details are given in Annexure.

Annexure

Annexure refer to Question No. 270 for answer on 25.11.2014

Sl. No.	State	Existing Area under Oil Palm	New oil palm area expansion target (in ha.) during 2014-15	Funds outlay for 2014-15 (Rs. in crores)
1.	Andhra Pradesh	1,30,531	14000	44.80
2.	Telangana	14,796	2000	7.45
3.	Karnataka	31,549	3100	10.13
4.	Tamil Nadu	22,854	1800	3.50
5.	Gujarat	4,196	450	1.29
6.	Odisha	16,225	3000	18.42
7.	Kerala	5,740	500	0.92
8.	Chhattisgarh	412	250	0.95
9.	Mizoram	19,971	4000	11.88
10.	Assam	10	1000	3.60
11.	Nagaland	0	1500	0.90
12.	Arunachal Pradesh	0	1600	2.44
13.	Meghalaya	0	1000	0.51
14.	West Bengal	0	550	0.52
15.	Other States	4,479	0.00	0.00
	Total	**2,50,763**	**34750**	**107.31**

******

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 270

25 नवम्बर, 2014 को उत्तरार्थ

विषय: पाम की खेती

270. डा. नैपाल सिंहः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में पाम की खेती को बढ़ाने की कोई योजना प्रतिपादित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे पाम का उत्पादन बढ़ाने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ0 संजीव कुमार बालियान)

(क) से (ग): जी हां । देश में आयलपाम की खेती के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने 1991-92 से 2003-04 से आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी), 2004-05 से 2013-14 से समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का योजना (आईसोपाम) तथा 2011-12 से 2013-14 तक आयलपाम क्षेत्र विस्तार (ओपीईए) का कार्यान्वयन किया । XIIवीं पंचवर्षीय योजना में 2014-15 से राष्ट्रीय तिलहन और आयलपाम मिशन (एनएमओओपी) कार्यान्वित किया जा रहा है ।

एनएमओओपी के मिनी मिशन-II (आयलपाम) के तहत रोपण सामग्री की खरीद, परिपक्वता अवधि के लिए अनुरक्षण, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना, डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प सेटों, बोर वेल/जल संचयन संरचना/तालाब, आयलपाम फील्डों में अन्तर फसलन के लिए आदान, वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, नये बीज बाग की स्थापना, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद और पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों/वाम स्कंध क्षेत्रों में आयलपाम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है । आयलपाम अनुसंधान निदेशालय (डीओपीआर), पेडावेगी, आईसीएआर कार्यान्वयक राज्यों को तकनीकी निर्देश तथा आयलपाम की रोपण सामग्री की आपूर्ति भी प्रदान कर रहा है ।

आयलपाम खेती के तहत क्षेत्र 1991-92 में 8,585 हैक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 2,50,763 हैक्टेयर हो गया है । इसी तरह वर्ष 1992-93 के दौरान ताजे फलों के गुच्छे (एफएफबी) और क्रूड पाम आयल (सीपीओ) का उत्पादन क्रमशः 21,233 एमटी और 1,134 एमटी था जो अब वर्ष 2013-14 के दौरान एफएफबी 9,95,211 एमटी तथा सीपीओ 1,71,354 एमटी बढ़ गया है । वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने 14 राज्यों में आयलपाम के तहत 34,750 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । राज्यवार विवरण अनुबंध पर है ।

अनुबंध

अ.प्र.सं.270

क्र. सं.	राज्य	आयलपाम के तहत विद्यमान क्षेत्र	2014-15 के दौरान नया आयलपाम क्षेत्र विस्तार लक्ष्य (है0 में)	2014-15 के लिए निधियां परिव्यय (रू0 करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	1,30,531	14000	44.80
2.	तेलंगाना	14,796	2000	7.45
3.	कर्नाटक	31,549	3100	10.13
4.	तमिलनाडु	22,854	1800	3.50
5.	गुजरात	4,196	450	1.29
6.	ओडिशा	16,225	3000	18.42
7.	केरल	5,740	500	0.92
8.	छत्तीसगढ़	412	250	0.95
9.	मिजोरम	19,971	4000	11.88
10.	असम	10	1000	3.60
11.	नागालैंड	0	1500	0.90
12.	अरूणाचल प्रदेश	0	1600	2.44
13.	मेघालय	0	1000	0.51
14.	पश्चिम बंगाल	0	550	0.52
15.	अन्य राज्य	4,479	0.00	0.00
	कुल	2,50,763	34750	107.31